भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3852**

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

रुपए के अवमूल्यन का मुद्रास्फीति और आवश्यक आयात पर प्रभाव

**3852.** श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रुपए के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति और आवश्यक आयातों पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरीकी प्रशुल्क से प्रभावित होने वाले उद्योगों की सहायता के के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ग) डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बाहरी आघात से बचाने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) रुपये के अवमूल्यन से निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। दूसरी ओर, अवमूल्यन आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा सकता है। आयातित इनपुट पर निर्भर उद्योगों को लागत संबंधी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, घरेलू कीमतों पर विनिमय दर अवमूल्यन का समग्र प्रभाव घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों के पास-थ्रू की सीमा पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के अलावा, आयात कई अन्य कारकों द्वारा निर्धारित किया किया जाता है, जिनमें वैश्विक आपूर्ति-मांग की स्थितियां, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, घरेलू मांग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण जैसे कारक शामिल हैं, जो उत्पादन और निर्यात के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात की आवश्यकता पैदा करते हैं। इस प्रकार, आयात के स्तर, आयात की लागत और इसलिए घरेलू मुद्रास्फीति पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता है।

(ख) अब तक, भारत पर अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ लागू नहीं किए गए हैं। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को संवर्धित करने और व्यापक बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ जुड़े हुए है. दोनों देशों ने 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, वर्ष 2030 तक दोनों देशों का लक्ष्य अमेरिका-भारत व्यापार को दोगुना से अधिक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, जिसे कई क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करके हासिल किया जा सकता है। दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की योजना बनाई है। दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

(ग) भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजार को इसका व्यवस्थित कार्यकरण और विकास सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करता है और केवल भारतीय रुपये में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। आरबीआई दुनिया भर में प्रमुख घटनाक्रमों की निगरानी करता है जिसका प्रभाव अमेरिकी डॉलर-रुपये की विनिमय दर पर पड़ सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई, दुनिया भर में प्रमुख आर्थिक डेटा जारी करना और उनके प्रभाव, ओपेक + बैठक के निर्णय, भू-राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखना और उनका विश्लेषण करना, जी-10 और ईएमई मुद्राओं में दैनिक उतार-चढ़ाव आदि शामिल हैं।

*****